सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) 16 जुलाई 2025 को डिजिटल सशक्तिकरण के 16 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव मनाएगा

- केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत एक अग्रणी पहल, कॉमन सर्विसेज सेंटर (सीएससी), 16 जुलाई 2025 को यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, द्वारका, नई दिल्ली में अपना 16वां स्थापना दिवस मनाएगा।

- सीएससी विगत 16 वर्षों में दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल सेवा वितरण नेटवर्क में से एक बन गया है, जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 6.5 लाख से अधिक केंद्रों के माध्यम से संचालित हो रहा है।
- कार्यक्रम में सीएससी के भविष्य की कार्ययोजना को भी प्रदर्शित किया जाएगा, जो विस्तृत पहुँच, सेवा विस्तार और प्रौद्योगिकी-आधारित नवाचार पर केंद्रित है।
- इस नए चरण में एआई-आधारित सेवाओं, क्लाउड समाधानों और डिजिटल रूप से सक्षम आजीविकाओं का एकीकरण शामिल होगा, जिसका उद्देश्य सीएससी को ग्रामीण नवाचार और आत्मनिर्भर भारत के केंद्र के रूप में विकसित करना है।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी के एक आदर्श के रूप में, सीएससी डिजिटल शासन, नागरिक-केंद्रित वितरण और सामुदायिक परिवर्तन की आधारशिला बन गया है।

सीएससी और सहकारी क्षेत्र

- वर्ष 2022 में, सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थिति में, सीएससी ने नाबार्ड और सहकारिता मंत्रालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत, देश भर की सहकारी ऋण समितियाँ अब सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) के रूप में कार्य करने लगी हैं।

- इस भागीदारी के बाद, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) और लैम्प्स (वृहद क्षेत्र बहुउद्देश्यीय समितियों) को सीएससी आईडी प्रदान की गई और उन्हें व्यापक प्रशिक्षण दिया गया।
- प्रशिक्षण पूरा करने के बाद, इन समितियों ने अपने-अपने राज्यों के दूरदराज के क्षेत्रों में सीएससी सेवाएँ प्रदान करना शुरू कर दिया।
- इस सहयोग का उद्देश्य ग्रामीण समुदायों के एक बड़े वर्ग को सशक्त बनाना और पैक्स (पीएसीएस) को वित्तीय रूप से सशक्त बनाना है।
- औसतन, प्रत्येक समिति में लगभग 500 सदस्य होते हैं। यदि कोई समुदाय अच्छी प्रगति करता है, तो लाभ सबसे पहले इन 500 व्यक्तियों या परिवारों तक पहुँचता है।
- इससे व्यापक प्रभाव पड़ता है, नेटवर्क का विस्तार होता है और सीएससी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए पंजीकरणों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होती है।

सामान्य सेवा केंद्र: अंतिम छोर तक पहुंच से लेकर भविष्य के लिए तैयार सेवाओं तक

- सीएससी एसपीवी की स्थापना वर्ष 2006 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के तहत की गई थी, जिसका उद्देश्य अंतिम छोर तक डिजिटल सेवाएं पहुंचाना और पूरे देश में एक सशक्त आईसीटी-आधारित नेटवर्क बनाना था।
- प्रत्येक सीएससी का प्रबंधन एक ग्राम स्तरीय उद्यमी (वीएलई) द्वारा किया जाता है, जो एक स्थानीय निवासी होता है और सरकार और नागरिकों के मध्य डिजिटल और सेवा सेतु का काम करता है।
- ये केंद्र आधार नामांकन और अद्यतन, पैन कार्ड प्रक्रिया, पासपोर्ट आवेदन, डिजी-पे और बीसी मॉडल के माध्यम से बैंकिंग और बीमा सेवाएँ, ई-संजीवनी के माध्यम से टेलीमेडिसिन, टेली-लॉ पहल के तहत कानूनी सेवाएँ, पीएमजीदिशा डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण, और बिजली-पानी के बिल भुगतान जैसी विभिन्न उपयोगिता सेवाओं सहित कई आवश्यक सेवाएँ प्रदान करते हैं।
- छात्रों को परीक्षा पंजीकरण, छात्रवृत्ति आवेदन और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में भी सीएससी सहायता प्रदान करते हैं।

समावेशी डिजिटल भारत के लिए दृष्टिकोण

- सीएससी ने ग्रामीण भारत में नागरिकों, विशेषकर महिलाओं, किसानों और वंचित समुदायों को उनके घर-द्वार पर डिजिटल पहुँच, वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य सेवा और आजीविका सहायता प्रदान करके, उन्हें सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- सीएससी पारिस्थितिकी प्रणाली में डिजिटल शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण के लिए सीएससी अकादमी; ग्रामीण ई-कॉमर्स को प्रोत्साहन देने के लिए सीएससी ग्रामीण ई-स्टोर; और विशेष रूप से कृषि एवं शिल्प में स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को सहायता प्रदान करने वाले कार्यक्रम जैसी पहल शामिल हैं।
- देश में सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं की एक व्यापक सूची निम्नलिखित है:

सरकार से नागरिक (जी2सी) सेवाएँ

- आधार नामांकन और अद्यतन
- पैन कार्ड आवेदन
- पासपोर्ट सेवाएँ
- जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन
- डिजिलॉकर सेवाएं
- बिल भुगतान (बिजली, पानी, गैस, आदि)
- नगरपालिका सेवाएँ (जैसे, संपत्ति कर भुगतान)

वित्तीय समावेशन सेवाएँ

- • बैंकिंग (विभिन्न बैंकों के व्यवसाय अभिकर्ता के माध्यम से)
- • डिजीपे - आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस)
- • बीमा सेवाएँ (पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई, जीवन एवं सामान्य बीमा)
- • पेंशन सेवाएँ (जैसे, अटल पेंशन योजना, एनपीएस, जीवन प्रमाण पत्र)
- • ऋण सुविधा और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सहायता

Result Mitra

शिक्षा और कौशल विकास

- सीएससी अकादमी (कौशल प्रशिक्षण, ऑनलाइन पाठ्यक्रम)
- एनआईओएस और इग्नू पंजीकरण और सेवाएँ
- सीएससी ओलंपियाड

स्वास्थ्य सेवाएँ

- टेलीमेडिसिन सेवाएं
- आयुष्मान भारत (पीएम-जेएवाई) पंजीकरण और सहायता

कृषि और संबद्ध सेवाएँ

- किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) आवेदन
- पीएम-किसान पंजीकरण और लाभार्थी सहायता
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड और फसल बीमा
- सीएससी ग्रामीण ई-स्टोर के माध्यम से कृषि-इनपुट बुकिंग
- किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) सहयोग
- टेली-कृषि और कृषि सलाह

डिजिटल सेवाएँ और उपयोगिताएँ

- सीएससी ग्रामीण ई-स्टोर (ग्रामीण उत्पादों के लिए ई-कॉमर्स)
- एलईडी बल्ब वितरण (उजाला योजना)
- रिचार्ज और डीटीएच सेवाएं
- मोबाइल और डीटीएच रिचार्ज

विधि और शासन सेवाएँ

- टेली-लॉ: विधि परामर्श और सेवाएँ
- ईस्टैम्प और दस्तावेज़ पंजीकरण

अन्य उल्लेखनीय सेवाएँ

- यात्रा बुकिंग (ट्रेन, बस, हवाई सेवा)
- होटल बुकिंग और यात्रा पैकेज
- आईआरसीटीसी एजेंट सेवाएँ
- मोबाइल फोन और सहायक उपकरण बिक्री

निष्कर्ष:

- सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) ने पिछले 16 वर्षों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में जबरदस्त कार्य किया है। सीएससी ने न केवल सरकारी सेवाओं को आम नागरिकों तक पहुँचाया, बल्कि वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में भी अहम भूमिका निभाई है। इसके जरिए ग्रामीण इलाकों में लोगों को बैंकिंग, टेलीमेडिसिन, शिक्षा, और सरकारी सेवाओं की सुविधा घर बैठे मिल रही है।
- सीएससी की पहल में ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और किसानों की मदद के लिए कई परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें कृषि से जुड़ी सेवाएं, किसान क्रेडिट कार्ड, और पीएम-किसान योजना जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। इसके अलावा, सीएससी ने शिक्षा और कौशल विकास में भी मदद की है, जिससे युवाओं को नए अवसर मिल रहे हैं।
- आगे बढ़ते हुए, सीएससी को डिजिटल सेवाओं का और अधिक विस्तार करने, एआई और क्लाउड समाधानों को अपनाने, और ग्रामीण क्षेत्रों में नए प्रकार की सेवाओं को लाने की दिशा में काम करना होगा। इसका लक्ष्य सिर्फ सेवाएं उपलब्ध कराना नहीं बल्कि डिजिटल सशक्तिकरण के साथ ग्रामीण समाज को आत्मनिर्भर बनाना होना चाहिए।

UPSC Mains अभ्यास प्रश्न :

- प्रश्न 1: "सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सशक्तिकरण और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस संदर्भ में, सीएससी की भूमिका और भविष्य की कार्ययोजना पर चर्चा करें। साथ ही, किस प्रकार से यह डिजिटल सेवाएं भारत के ग्रामीण इलाकों में आत्मनिर्भरता और समावेशन को बढ़ावा दे सकती हैं?"

UPSC पिछले वर्ष के प्रश्न:

- प्रश्न: "भारत में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा करें।" (UPSC 2019)
- प्रश्न: "डिजिटल इंडिया क्या है? यह भारत के ग्रामीण क्षेत्रों को कैसे परिवर्तित कर रहा है?" (UPSC 2016)

यूपीएससी प्रिलिमस: 2024

- प्रश्न: डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- 1. इस योजना को लागू करने के लिए, केंद्रीय सरकार 100% वित्त पोषण प्रदान करती है।
- 2. योजना के तहत, काडेस्ट्रल मानचित्रों को डिजिटाइज़ किया जाता है।
- 3. अधिकार अभिलेखों को स्थानीय भाषा से संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में ट्रांसलिटरेट करने की पहल की गई है।

उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 2
- (d) 1, 2 और 3 ।

- उत्तर : d (1, 2 और 3)